



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 123]  
No. 123]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 1988/ज्येष्ठ 26, 1910  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 1988/JYAISTHA 26, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

मार्बजनिक् सूचना सं. 19 आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 16 जून, 1988

विषय: —1987-88 के लिए 1.254 बिलियन येन (ऋण सहायता)  
का जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत मार्बजनिक् क्षेत्र के  
आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मि. सं. आई पो 23/सी (29)/85-88:- 1987-88 के लिए  
1.254 बिलियन येन (ऋण सहायता) जापानी अनुदान सहायता के  
अंतर्गत आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस के लिए लागू होने वाली शर्तें जो  
इस मार्बजनिक् सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधि-  
सूचित की जाती हैं।

राजीव लोचन मिश्र, सहाय निर्यात, आयात व निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की मार्बजनिक् सूचना सं. 19-आई टी सी (पी  
एन)/88-91, दिनांक 16-6-88 का परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1987-88 के लिए येन 1.254  
बिलियन (येन 1,254,922,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान  
सहायता के अंतर्गत मार्बजनिक् क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें  
खण्ड-1 सामान्य शर्तें:

1 (1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1.254  
बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा ओ.ई.सी.डी.  
और विकसशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस  
ऋण के अधीन अधिप्राप्त होने वाली पाय वस्तुएं और उनमें संबंधित  
प्रारंभिक सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों में  
आयात की जा सकती हैं। वे देश इस अनुदान के अंतर्गत पात्र श्रोत देश  
होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती  
हैं उनकी सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

1 (2) लाइसेंस पर एक शीर्षक 1987-88 के लिए "येन 1.254  
बिलियन जापानी अनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के

लिए लाइसेंस संकेत "एम/जे.एन." होगा। ये प्रत्यक्ष मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात के लिए आयात लाइसेंस के अप्रैप्ट पत्र में भी दृष्टांत जायेंगे।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किन्हीं भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकारियों के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकारियों को भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के दो भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस का वैधता में वृद्धि के लिए, लाइसेंसधारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (ज्ञान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित जापान का अर्थ पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर) अपर सचिव (टो.सी.) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए उन त्रय आदेशों से है जो भारतीय लाइसेंसधारियों से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत गमपित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकारियों के आदेश और/या भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके। इन कारणों का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीने से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निष्पादित रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ज्ञान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने जिससे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत-व्यय के लिए अप्रैप्ट निधि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह निधि 31-3-1989 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संलग्न ठेके का समझौता करने योग्य ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें—

2(1) (क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू.एस. डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक पेन, एक सेंट या एक पेनी में कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अधिकारियों का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए।

जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदत्त की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नगद आधार पर अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) त्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3

संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए—

3(1) 1987-88 के लिए येन 1.254 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा का व्यवस्था 18-2-88 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार को गई है जो भारत सरकार के अनुमोदन की शर्तों के अधीन होगी।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (एपी)" के माध्यम से किया जाएगा जो 1987-88 के लिए जापान अनुदान सहायता के अर्धत बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा निर्यातक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू.सी.आ. बैंक बिल्डिंग पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार हैं और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्ग के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4 भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन—

4(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं लाइसेंस-धारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्रपार संभरकों का भारतीय आयातक द्वारा दिए गए त्रय आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-3 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियां सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अपर सचिव (टो.सी.) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जाएगी। उपर्युक्त एफिया संविदा को विषय-वस्तु या उसकी कोमत के आवश्यक संशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए लागू होगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिए आवेदन-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट का सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने के व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी से प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो-आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो, जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अग्रगण्य करेगा।

4(5) पातलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकों के माध्यम से संभरक को दस्तावेजों में निदिष्ट धनराशि को रिजर्व करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देश बैंक खर्च, भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड-5 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध-3 में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात की सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू.एम. डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर विदेशी, संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत की प्रतिवर्ष दर से हिमाव लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, 10-8-83 सं. 35/आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-86 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 भुगतानों की येन/यू.एम. डालर/पौंड धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अग्रणी जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की गति पर

होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रक परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा ममान-मम पर अधिवृत्ति हो जाएगी। इन संबंध में जारी हो परिपत्रों जब और जैन हो आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इन बात की सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि असाधारण परिस्थितियों में सामाजिक प्राधिकारियों से मूल पोत-परिवहन दस्तावेजों के बिना माल का विवरण प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा करा दी गई है जिन लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह है डिपॉजिट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिपॉजिट्स - डिपॉजिट्स फॉर परेपेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंड (कृप्य सहायता)।

5(3) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने और कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली में सरकार को माघ में नकद जमा होनी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इनके उप-शाखा किंग में राष्ट्रीय बैंक (टुल्डोकर्ता) से प्राप्त एक टुण्डो (डिपॉजिट ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (टुण्डो ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन) 76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन-प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिश्चित धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालों को भरने समय आयातकों/उनके बंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 2-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक, 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 में भी निर्धारित सूचना चालान के कांजम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण तरीके से निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्याज निरपवाद रूप से प्रस्तुत करना चाहिए:-

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं. और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निवेश किए गये हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह प्रवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(व्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में समुचित रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है)।

उसके पञ्चात् सी.ए.ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देने हुए और बोज़त तथा पात परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान द्वारा जमा करने का माथा देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी.ए.ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत के आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अराधनी की सूचना और अपरिवर्तनीय पानलदान दस्तावेजों को प्राप्त के दस दिनों के भीतर निरववाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी.ए.ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में सबसे बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर दया निवेदों को धारणा का पृष्ठिका करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रात भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड-6 विविध शर्तें:—

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट:—

\*आयातक को आयात किए गए भुगतान की राशि और निशि का पता करने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आयातक के क्लृप्तदान द्वारा पात परिवहन आदि दस्तावेजों की वाद में या देश से प्राप्त का रूपया निक्षेप पर देय ब्याज की आंशिक या पूरी धनराशि को माफ करने के लिए बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरकों को अवगत कराये जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों में पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त माफ-माफ भुगतान के नियमन के अन्तर्गत अनुबद्ध 1 में दर्शाई जाती चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें टेके में शामिल होती चाहिए।

6(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित जागत से 1987-88 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभागों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अनिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गयी शर्तों के अनिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।

6(6) अनुबंधों की सूची:—

- |          |  |
|----------|--|
| अनुबंध—1 | पात स्रोत देशों की सूची  |
| अनुबंध—2 | पात पुण्य वस्तुओं की सूची  |
| अनुबंध—3 | भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र |
| अनुबंध—4 | भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।                            |

\*आयातक को पानलदान और उसके मद्दे भुगतान और वक्राया यह गई धनराशि में संबंधित एक मासिक रिपोर्ट अधिकार पत्र जारी करने के बाद सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ. बैंक विंडिंग, संवर मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

पात स्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी डी देश

आस्ट्रेलिया	बेलजियम
कनाडा	डेनमार्क
फिनलैंड	फ्रांस
जर्मनी संघीय गणराज्य	यूनान
आइसलैंड आयरलैंड	इटली
जापान	लगजमबर्ग
दी नीदरलैंड	न्यूजीलैंड
नार्वे	पुर्तगाल
स्वीडन	स्वीटजरलैंड
स्वीटजरलैंड	तुर्की

दि यूनाइटेड किंगडम और युनाइटेड-स्टेट्स

(ख) विकसनीय देश तथा उनके क्षेत्र

(ख-1) —नात-ओ.पी.ई.सी. विकसनीय देश

1. अफ्रीका उत्तरी महाप्रा

मिश्र	मॉरक्को
तुनीशिया	

2. अफ्रीका दक्षिणी महाप्रा

अंगोला	बोत्सवाना
बुरुंडी	कैमरून
केपवर्डी द्वीप समूह	केंद्रीय अफ्रीकन गणतंत्र
कांड	कमोरो द्वीप समूह
कांगो, दमोह गणराज्य	(1) इक्वेटोरियल गार्डना
इथोपिया	ज़ाम्बिया
घाना	मेट हेल्सि और डेप (2)
गुयाना	सांटोन प्रिन्सीपि
आइरी कोस्ट	सेनेगाल
केन्या	मिचिनीज
निजोत्री	सियरा लियोन
लाइबेरिया	सोमालिया
मालागामी गणतंत्र	सूडान
मलावी	स्वाजीलैंड
मार्तिनिया	टेरो अक्वस और इत्याल
मार्शाल	टोंगो
मोजाम्बीक	युगाण्डा
नाइजर	तंजानिया गणतंत्र संघ
पुर्तगाल गिनी	अपर वोल्टा
रि-यूनियन	जायरे गणतंत्र
रोडेणिया	ज़ाम्बिया
स्वान्डा	

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश करनेवां द्वीप समूह।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित अमंगोन, टिस्टन ला डन एक्सेगिबिया, नाइटीगेल, गणप।

(3) ऐन समूह, अरवा, बोनाहरे, क्याराकाओ महा, सेंट यूस्टामिट, सेंट मार्गटन (दक्षिणी भाग)

## 3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमन	डोमिनिकन गणतन्त्र
बारबाडोस	एल साल्वाडोर
बेलाइज	गुवाटेमाला
बरमुडा	ग्वाटेमाला
कोस्टारिका	हेती
क्यूबा	हॉन्डुरस
जमैका	निकारागुआ
माटिनिकक्यू	पनामा
मैक्सिको	सेन्ट पियरी और मिक्युलोन
नीदरलैंड एंटीलीज	ट्रिनिडाड टोबागो
वेस्ट इण्डोज (बा.) एन. आई. ई.	

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) आश्रित राज्य (2)

## 4. दक्षिणी अमेरीका

अर्जेन्टीना	फार्मोसी गिनी
बोलिविया	गुयाना
ब्राजील	पाराग्वे
चिली	पेरू
कोलम्बिया	सूरिनाम
फगनकलैंड द्वीप समूह	उरुग्वे

## 5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन	सिरियाई अरब गणतन्त्र
इजराइल	यूनाइटेड अरब एमिरात
जोर्डन	यमन अरब गणतन्त्र (3)
क्षेत्रान	यमन जनवादी डी. आर. (4)
ओमन	

## 6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान	मालदीव
बांग्लादेश	नेपाल
भूटान	पाकिस्तान
बर्मा	श्री लंका

## 7. सुदूर पूर्व एशिया

बुर्नेई	मिंगापुर
हांगकांग	ताइवान
खम्वर गणतन्त्र	थाइलैंड
लाओसका कोरिया गणतन्त्र तिमोर	
मकाओ	वियतनाम गणतन्त्र
मलेेशिया	वियतनाम जनवादी गणतन्त्र
फिलीपाइन	

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, टोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफ़), नेविस अंगुइला, सेन्ट लूसिया और सेन्ट विसेन्ट।

(2) मेन आईलैंड, मोल्तये रेंट, वेमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह।

(3) आईजुमन, दुबई, फजाराह, राम अत खैमाह शेरजाह और उम्मत खैवत

(4) अदन और विभिन्न गलतल और असाधारण सहित।

(5) सोगाइटी, आईमलूइस समूह (ताहिती सहित) को शामिल करने हुए अस्ट्रल द्वीप समूह, दुआमोंट, जांविनर गुप और माकेपल द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रेक्ष, कारोरीन द्वीप समूह, माकेल द्वीप समूह और पैसिफिक द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

## 8. ओशनिया

कोक द्वीप समूह	हिगू
फिजी	पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) यू.एस. (6)
गिन गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप	पापुआ न्यू गिनी
फांनोमी पोलिनेशिया (5)	मोनाको द्वीप समूह (हि.)
नारु	टोंगा
न्यू कोलेडोनिया	वालिस् और फूतुना
न्यु केप्रिसेम (ब. और प्र.)	--पश्चिम समाओ

## 9. यूरोप

माइप्रम	स्पेन
जिब्राल्टर	तुर्की
ग्रीक	यूगोस्लाविया
माल्टा	

खण्ड-2--ओ.पी.ई.सी. के सदस्य या सहयोगी देश।

अल्जीरिया	बेन्गुएला
बोलिविया	ईरान
बोवियाई अरब गणतन्त्र	ईराक
गेवान	कुवेत
नाइजीरिया	कातार
इराक	सऊदी अरब
	इन्डोनेशिया
	आबू धाबी

पात्र पक्ष सूची

## 1. रोज़न

## 2. विशेष इरात और मिथ-गाल इरात सहित इरात

3. टूफा और टूटरा के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुनः।

## 4. रमेश्वर

5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुज, संघटक, और कच्चा माल।

6. विजली के हकों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुज

7. मशीनरी, संघटक, संयोजक, फालतू पुज और कच्चा माल

8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपकरण

9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपकरण और फालतू पुज।

10. उर्वरक और गैसी अन्य मदे, जिन पर आपस में सहमति हो।

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र”

मं.

दिनांक

सेवा में

सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा निदेशक,  
वित्त मंत्रालय,  
आर्थिक कार्य विभाग,  
यू.सी.ओ. बँक बिल्डिंग,  
प्रथम मंजिल,  
पार्लियामेंट स्ट्रीट,  
नई दिल्ली-110001

विषय :- 1987-88 के लिए येन 1.251 बिलियन जापानी ऋण अनुदान सहायता घेन के अर्धीन जापान से आयात।

महोदय,

उपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अर्धीन जापान से जो कि... आयात के सम्बन्ध में है संबद्ध संभरक के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको निम्नलिखित ध्येय प्रस्तुत करने हैं :-

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके -- क्या यह सीधे कर या औद्योगिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेत होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्माण उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय सरा में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) संभरकों के साथ की गयी संविदा की संख्या और दिनांक

(डा) संभरक का नाम और पता

(ट) ये भुगतान शर्तें और समाविष्ट निधि जिनकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) सुपुर्दगी की पूर्ण करने की प्रत्यागित तिथि।

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय कि, जाने वाले दस्तावेजों (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करे) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए।

(ढ) पोत लदान अनुदेश (वाहनानुदेश/पोर्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट की जाए।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(न) क्या उर्मी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है। यदि हां, तो ऐसी संविदा का दिनांक और मूल्य।

(य) वह भारतीय पन्ना जहां उपकरण/माल का पोतलदान किया जाना है।

भवदीय

अनुबन्ध-1

सदृश

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,  
टोकियो शाखा,  
टोकियो (जापान)

विषय :- येन 1.251 बिलियन के लिए जापान ऋण अनुदान सहायता के अर्धीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के पास दिनांक-----को दिए गए करार के नियम और शर्तों के अनुसार आपको एन्डोर्समेंट-----  
(परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)

-----येन तक की धनराशि को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावनों के बारे में संभरकों को सूचना दे और उनके प्रत्येक सूचना पर की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजस्व विभाग, टोकियो और इस मंत्रालय का पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में क्या संकेतित लदान दस्तावेजों के आधान पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने के बाद, आपका----- (आयातक के बैंक का नाम और पता) को सभी मूल पोत परिवहन दस्तावेजों (परकाम्प) और उनके साथ-साथ दस्तावेजों के प्रतिरिक्त पूरे सेट और यदि कोई नक्कल भुगतान किया गया हो तो उनके सहित संभरक को दिए गए भुगतान के ऋण पर की एक प्रति भेजनी चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपके दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए नवान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संवाख्य और आयातक के बैंक को भेजी जाएगी।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए अधिकार पत्र के लिए कोई भी संगोपन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र-----तक वैध रहता है।

9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में और भुगतान दर्शाने वाले बीजक में भी भुगतान के लिए इस प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या को कोड करें।

भवदीय,

लेखा अधिकारी,

प्रति प्रेषित है :-

1. आयातक-----को उसके पत्र सं.-----दिनांक-----के मदर्भ में।

(1) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अधीन आयातों को नियंत्रित करने वाली संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। लाइसेंसिंग शर्तों और संबद्ध सार्वजनिक सूचनाएं/और आदेशों आदि का अनुवीक्षण किया जाए और संबंधित आयात/विदेशी भुगतान के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

2. आय तक का बैंक-----उससे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को यें/यू एम डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के रूप की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिति दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेख में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 और 35-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेख में जमा कराना होगा व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेख में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमा शुल्क निर्याती के लिए आयात दस्तावेजों का मूल भेंट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

3. येन धनराशियां चालान के दाहिने ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुपंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, बिल्लो-6 (आदेशित और आदात) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 23-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 मिबिल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार एरचेजिज्म एरसेकट्रा एक्वाइ-एरचेजिज्म ग्रैंड एंड फार्म दि गवर्नमेंट आफ जपान फार 1987-88 (येन 1.254 बिलियन ग्रैंड एंड डेबिट रिलीज)।

(4) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद-जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रपेण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :-

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यूमीओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

(5) जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करता है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में व्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपया का पूरा व्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(6) सन्दर्भ संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च इंडियन बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

(7) विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक के कार्य और जिम्मेदारियां भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए.डी. परिपत्रों में निर्धारित हैं। इस संबंध में विशेष संदर्भ ए.डी. परिपत्र सं. 22, दिनांक 18-6-87 का दिया जाता है।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो,

5. अवर सचिव (टी ए) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी,

## MINISTRY OF COMMERCE

## IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 19-ITC(PN) 88-91

New Delhi, the 16th June, 1988.

Subject :—Licensing conditions in respect of Public Sector Imports under Japanese Grant Aid of Yen 1,254 Billion (Debt Relief) for 1987-88.

File No. IPC/23(28)/85-88.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1,254 Billion (Debt Relief) for 1987-88 in respect of Public Sector imports, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

R. L. MISRA,

Chief Controller of Imports &amp; Exports.

Appendix to the Ministry of Commerce Public Notice No. 19 ITC(PN) 88-91 dt. 16-6-88.

**LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER JAPANESE GRANT AID OF YEN 1,254 BILLION (1,254,922,000) (DEBT RELIEF) FOR 1987-88 EXTENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN**  
Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 1,254 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 1,254 billion Japanese Grant Aid for 1987-88." The licence code for the first and second suffix will be "SJN". These will be also repeated in the letter from the CCI&E forwarding the licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the

date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas suppliers duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licensing authorities who may grant further extension upto a maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it shall be noted that this date should not be beyond 31-3-1989.

**Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract**

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.



## II (iii) Eligibility of Supplier.

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

## Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated 18-2-88 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.254 billion for 1987-88 “and will be subject to the approval of Government of India.”

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an ‘Authorisation to Pay’ (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New-Delhi-110001 in favour of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1987-88.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

## Section IV—Contract Approval by Govt. of India.

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier or their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the request for issue of “A/P” in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contracts amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents “Request for issue of A/P” and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an ‘Authorisation to pay (A/P)’ to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer’s Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer’s Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his banker, the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer’s Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India’s account.

## Section V—Responsibility for rupee deposit

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer’s bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|US\$|Pound sterling payments made to the supplier along with interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 per annum for the first thirty days and at 18% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN) 83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC(PN) 83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i. e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN) | 74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN) |76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|US\$|£ payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN) |76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Central Circulars of the Reserve Bank of India. Any changes in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and

when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amount due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licence should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1987-88 (Yen 1,254 billion Grant Aid-Debt-Relief).

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan are in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN) |68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN) |68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC (PN) |71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC (PN) |74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN) |76 dated 12-10-1976.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN) |71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC (PN) |74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC (PN) |76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' ( Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

#### (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

#### SECTION—VI Miscellaneous provisions.

##### VI (i) \*\* Reports on the utilisation of the import Licence.

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

##### VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licence should appraise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

##### V. (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

##### VI. (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1987-88 from Japan.

## VI. (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

## VI (vi) List of Annexures

Annexure-I.—List of eligible source countries.

Annexure-II.—List of eligible commodities.

Annexure-III.—Form of Request for issue of Authorisation to pay (a A/P).

Annexure-IV.—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

\*\* The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

## ANNEXURE-I

## LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

## A. OECD COUNTRIES

Australia.  
Belgium.  
Canada.  
Denmark.  
Finland.  
France.  
The Federal Republic of Germany.  
Greece.  
Iceland.  
Ireland.  
Italy.  
Japan.  
Luxembourg.  
Netherlands.  
New Zealand.  
Norway.  
Portugal.  
Spain.  
Sweden.  
Switzerland.  
Turkey.  
The United Kingdom and  
The United States.

## B. Developing Countries &amp; Territories.

## (b1) Non-OPEC Developing Countries.

## I. Africa, North of Sahara

Egypt.  
Morocco.  
Tunisia.

## II. Africa, South of Sahara.

Angola.  
Botswana.  
Burundi.  
Cameroon.  
Cape Vards Islands.  
Central African Rep.  
Chad.  
Comoro Islands.  
Congo, People's.  
Republic of Dahomay (1).  
Equatorial Guinea.  
Ethiopia.  
Gambia.  
Ghana.  
Guinea.  
Ivory Coast.  
Kenya.  
Lesotha.  
Liberia.  
Malagasy Republic.  
Malawi.  
Mali.  
Mauritania.  
Mauritius.  
Moozambique.  
Niger.  
Portugese Guinea.  
Reunion.  
Rhodesia.  
Rwanda.  
St. Helena and Dep (2).  
Sao Tome and Principe.  
Senegal.  
Seychelles.  
Siorra Loone.  
Somalia.

Sudan.  
Swaziland.  
Terro, Afars and  
Isses.  
Togo.  
Uganda.  
Un. Rep. of Tewasania.  
Upper Volta.  
Zaire Republic.  
Zambia.

Brazil.  
Chile.  
Colombia.  
Falkland Islands.  
French Guiana.  
Guyana.  
Paraguay.  
Peru.  
Surinam.  
Uruguay.

- (1) Formerly, the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Mall islands, Aruba, Fena'ra, Curacao, Saba, St. Eustacit, St. Martin Southern Part.

### III. AMERICA North & Cent.

Bahamas.  
Barbados.  
Belize.  
Barmuda.  
Costa Rica.  
Cuba.  
Dominican Republic.  
El Salvador.  
Guadeloupe.  
Guatemala.  
Haiti.  
Honduras.  
Jamaica  
Martinique.  
Mexico.  
Netherlands Atilles.  
Nicaragua.  
Panama.  
St. Pierr & Miquelon.  
Trinidad and Tobago.  
West Indies (Br.) n.e.e.

- (a) Associated States (1).
- (b) Dependencies (2).

### IV. AMERICA, South.

Argentina.  
Bolivia.

### V. ASIA, Middle East

Bahain.  
Isreal.  
Jordan.  
Lebanon.  
Oman.  
Syrian Arab Republic.  
United Arab Emirates (3).  
Yemen Arab Republic.  
Yemen, People's D.R. (4).

### VI. ASIA, South

Afghanistan.  
Bangladesh.  
Bhutan.  
Burma.  
Maldives.  
Nepal.  
Pakistan.  
Sri Lanka.

### VII. ASIA, Far East

Brunei.  
Hongkong.  
Khmer Republic.  
Korea, Republic of Laos.  
Macao.  
Malaysia.  
Phillipines.  
Singapore.  
Taiwan.  
Thailand.  
Timer.

Vietnam, Rep. of.

Vietnam Dem. Rep.

- (1) Main Islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main Islands : Montserrant, Gayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.
- (3) Iajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaiman, Sharjah and Ummal Quaiwain.
- (4) Including Aden and various Sultanates and Emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuametu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands and Marine Islands (except Guam).

#### VIII.

Cock Islands.

Fiji.

Gilbert & Ellice Is.

French Pelynesia (5).

Nauru.

New Calendoncia.

New Hebrides (Br. & Fr.).

Hieu.

Pacific Islands (US) (6).

Papua New Guinea.

Solomon Islands (Br.).

Tongo.

Wallis and Futuna.

Western Samoa.

#### IX. EUROPE

Cyprus.

Gibraltor.

Greece.

Malta.

Spain.

Turkey.

Yugoslavia.

- (b2) Member or Associate Countries of OPEC.

Algeria.

Bolivia.

Libyan Arab Republic.

Gabon.

Nigeria.

Ecuador.

Venezuela.

Iran.

Iraq.

Kuwait.

Qatar.

Saudi Arabia.

Abu Dhabi.

Indonesia.

#### ANNEXURE II

##### ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls.
2. Steel including special steel & alloy steel.
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.
4. Chemicals.
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers.
7. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
8. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas sector.
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

#### ANNEXURE III

##### "REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORIZATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street,  
New Delhi-110001.

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen 1,254 billion for 1987-88.

Sir,

In connection with the import of \_\_\_\_\_ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you

to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement. Whether it is based on direct purchase or formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of goods.
- (e) Origin of goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and address of the Supplier.
- (j) Name and date of the contract with Suppliers.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (incl. indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.
- (q) Indian Port to which the equipment/materials are to be shipped.

#### ANNEXURE—IV

No.

Government of India.  
Ministry of Finance.  
Department of Economic Affairs.  
New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Japanese Debt-Relief Grant  
Aid of Yen 1.254 billion—Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated \_\_\_\_\_ entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen \_\_\_\_\_ to M/s. \_\_\_\_\_ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importer's Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to \_\_\_\_\_ (Name & address of importers Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the document and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo Importer's Bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the Importer's bank.

7. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. The A/P will remain valid upto \_\_\_\_\_.

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer \_\_\_\_\_ with reference to their letter No. \_\_\_\_\_ dt. \_\_\_\_\_.

2. Importer's Banker \_\_\_\_\_.

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices/orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen/US\$/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate

of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notices No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dt. 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi, indicating code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1987-88 (Yen 1.254 billion Grant Aid-Debt Relief).

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dt. 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) 1st floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the public Notice dt. 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest 1 per cent and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised Dealer in foreign exchange are prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific references in this regard are invited to A.D. Circular No. 22 dt. 18-6-1977.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TC), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to ID No. ————|Jap dt. ———.

(Accounts Officer).

